[Mr Deputy-Spaker]

'for the period for which it had been made' *substitute* the words 'for the period of one year from the date of appointment'.

This House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do concur in this resolution.".

The motion was adopted.

17.04 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

Ministry of Irrigation and Power—*contd.*

Mr. Deputy-Speaker: We shall now revert to the discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Irrigation and Power.

श्री अचल सिंह (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इर्रीगेशन एंड पावर की बजट डिमांड्स चल रही हैं यह हमारे देश के लिए आवश्यक हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उस के 80 फीसदी आदमी कृषि का काम करते हैं। कृषि का काम पानी पर निर्भर करता है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ठीक ही बतलाया है कि बगैर पानी के कोई काश्त नहीं हो सकती है इसलिये इस मंत्रालय का काम यह होना चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा पानी सप्लाई करे चाहे वह डैम से हो, मेसोनरी वैल से हो, नहरों से हो, ट्यूबवैल्स से हो या तालाबों से हो। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए पानी की बड़ी आवश्यकता है।

हमारा उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। अगर उस में पानी की, बिजली की ठीक व्यवस्था हो जाय तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न की अपनी ही जरूरत नहीं पूरी कर लेगा अपितु काफ़ी अन्न पैदा कर के दूसरे राज्यों को भी सप्लाई कर सकता है। इस वक्त हमारे देश में अन्न की बहुत कमी है। हम को पिछले 15–16 वर्षों से अरबों रुपयों का अन्न बाहर से मंगाना पड़ा है और अभी भी हम भारी तादाद में बाहर से अनाज मंगा रहे हैं। अनाज की दृष्टि से इस वक्त देश में हालत बहुत अबतर है इसलिये अनाज का उत्पादन बढ़ाने की ओर हम को पूरा ध्यान देना चाहिए और उस के लिए जरूरी हो जाता है कि हम सिंचाई के वास्ते ज्यादा से ज्यादा पानी उपलब्ध करें।

मैं आप को बताऊं कि हमारे उत्तर प्रदेश को पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के वास्ते और पावर के वास्ते भी बहुत कम रुपया मिला है जिसकी कि वजह से हमारा राज्य बहुत बैकवर्ड है। यह स्टेट सरप्लस हो सकती है बशर्ते कि उसे पानी और पावर पर्याप्त मात्रा में मिले।

मैं आप को इस वक्त आगरा के बारे में बतलाना चाहता हूं कि आगरा और मथुरा ड्राई डिस्ट्रिक्ट हैं, डैफिसिट डिस्ट्रिक्ट हैं। वहां के लिए पिछले 15 सालों से मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जिले को पानी मिले। सरकार की ओर से कह दिया जाता है कि राम गंगा डैम बनेगा उस वक्त पानी मिलेगा। यह पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया और तीसरी में भी कहा गया। अब कहा जा रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जब यह डैम तैयार होगा उस वक्त पानी मिलेगा। जाहिर है कि बगैर पानी के काश्त नहीं हो सकती है। अगर और नहीं तो 100 ट्यूबवैल्स मिल जायें तो भी काम चल जाये लेकिन आज तक हमारे आगरा को वह नहीं मिले हैं। अब बगैर पानी के क्या हो सकता है?

आगरा जिले में बिजली आ गई है लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद इसके कि वहां पर बिजली आ गई है उस की लाइन दौड़ गयी है लेकिन

लोगों को बिजली के कनैक्शन नहीं मिल रहे हैं । जो लोग पैसा देते हैं उन को बिजली का कनैक्शन मिल जाता है बाक़ी लोगों को वह नहीं मिल रहा है । बिजली की कमी की वजह से उनको बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है । मैं अपने क्षेत्र में दौरे पर गया था तो मैंने देखा कि जिन लोगों ने अपने पैसे से छोटे छोटे ट्यूबवैल लगा लिये हैं डीजल इंजन से उन पर काम करते हैं । छोटा सा गांव पनवारी है वहां 13 ट्यूबवैल लग गये हैं और सात और लगने वाले हैं लेकिन वह डीजल आयल से चलते हैं क्योंकि बिजली मिली नहीं है ।

अभी हाल में देहातों में ट्यूबवैल्स, मेसोनरी वैल्स और रहट आदि लगाने के लिए रुपया दिया जाने लगा है पर किसानों को उस रुपये के मिलने में बहुत दिक्कत होती है । कोआपरेटिव्स वहां पर आ गयी हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन कोआपरेटिव्स से काश्तकारों को रुपया बड़ी परेशानी से मिलता है काफ़ी उनका खर्च हो जाता है, कुछ देना पड़ता है तब जा कर कहीं वहां से रुपया मिल पाता है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से यही कहूंगा कि यह आप बड़ा भारी काम करेंगे अगर देश में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में पानी का इंतजाम पर्याप्त तौर पर कर दें । बगैर पानी के कुछ भी नहीं हो सकता है । इस वक्त खाद की समस्या बहुत हमारे सामने लाई जा रही है लेकिन खाद भी तो तभी काम देगी जब पानी मिलेगा । अब खाद का काम तो हमारे यहां जो गोबर वगैरह है या और चीजें हैं उनसे भी पूरा हो सकता है लेकिन पानी की कमी किसी चीज से पूरी नहीं हो सकती है । इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह उत्तर प्रदेश के वास्ते पर्याप्त रुपया दें जिससे कि बिजली काफ़ी पैदा हो सके और पानी का भी इंतजाम हो सके । इस की बड़ी जरूरत है कि खास तौर से यह जो रामगंगा डैम है वह जल्द तैयार हों ताकि पश्चिमी जिलों को पानी मिल सके । मैं आशा करता हूं कि इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में काफ़ी रुपया उत्तर प्रदेश के वास्ते दिया जायगा जिससे जो कमी रह गयी है पिछली तीनों योजनाओं में वह बिजली और पानी की कमी पूरी हो जाये । मैं आशा करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इस पर पूरा ध्यान देंगे ताकि यू० पी० ज्यादा से ज्यादा गल्ला पैदा कर सके और देश की गल्ले की कमी को पूरा कर सके ।

Shri Gajraj Singh Rao (Gurgoan): Enough has been said on the activities of this Ministry. With the present sympathetic Minister, and the Minister of State, who is an expert on these matters, I think that the things which had been neglected for many, many years would receive sympathetic consideration. I submit that the irrigation canal scheme after the Hariana agitation in the united Punjab was conceded but they said Delhi has expanded and there could be the Gurgoan tunnel scheme. Later on they said that even the tunnel scheme is not possible as it would take so much time. For the last thirty years it has been pending and then there is the lift scheme. I am thankful to Dr. K. L. Rao who sympathetically examined the whole case and ordered that work should begin. But the implementation was with Punjab who somehow or the other are hostile to this neglected area. They did not implement it. It is in the knowledge of the hon. Minister. The manner and time in which he wanted the implementation was not carried out in the spirit of the promise.

I am again thankful to Dr. Rao who came out with a scheme for drainage of dirty water of Delhi. It was proposed to take it through Gurgaon district for fifty miles and the residential areas would have been affected. When he heard me and when I told him that there was a scheme approved by Shri Khosla and Rai Bahadur Sen

[Shri Gajraj Singh Rao]

noted international engineers, and that scheme would cost Rs. 40 crores, he suggested the Sahibi nadhi scheme and that drain water should be utilised for irrigation purposes; it would cost only Rs. 2 crores. It is still with the Punjab Government cold storage. It was not given effect to. The work on Gurgaon lift scheme should be expedited. Secondly, Sahibi scheme approved by the engineers of international fame should be given effect to. They should get at least drinking water. I need not dilate on these things further because it is within his knowledge. In these areas, the minor works were of great importance. There were small bunds as they were called; they were well administered when they were with the local authorities. Later on they were taken over by the government and they are neglected and not even maintenance is made properly according to the standards, and that is going to be a big problem.

The next point I want to urge is about electricity. It has been stated already that the big priority problem is agriculture. The basis for agriculture is irrigation. If that is to be solved, the resources should be tapped. Take Hariana for example. Some areas are flood areas; some are water-logged areas and some are absolutely dry areas. There was a scheme approved by the government of India that from the water-logged areas it should be drained out and supplied to absolutely dry areas which are famine areas every third year. So, I would submit that those things should be considered. Why this is so in regard to this area is well-known to the House. It was because of the first war of Independence that these things were carried on. They were victimised and that spirit is going on still, on paper—some papers are dealt with—and in the same spirit and in the same manner, they are going on. So, I would submit that if electricity is supplied to sweat water areas, the produce can be ten times more or even 15 times. It is on record that though some wells are 200 feet or 250 feet deep, very good water in abundance, is found in them. The Central Government has been giving money but that was not spent and it was returned, with the remark that they have no technicians for boring and so on. I submit that this kind of treatment should be given up. Electricity for the pumping sets should be given. As has been said, there are no connections given, though the line is there. It is argued that those people cannot pay to their lower staff there and they cannot get the collection. As a result of my speech in the last session, enquiries were made and it was found to be true. The villagers came, and they demand such and such amount for collection. Otherwise, they would not give the connection. Is it top priority for agriculture? If this is the spirit in which the work is going on, what can be done?

Take another instance. It is one of discrimination. The Agra canal starts from Delhi area, just about 15 miles from Gurgaon district, and the water rate is just double of what it is in Punjab. It was promised by the hon. Minister of Irrigation and Power that this would be rectified, and this is gross injustice done to these people. The canal starts here, and flows only for two miles in Delhi. They say there is no administrative control or even advisory control or advisory committee. What happens is—it has been perhaps verified by the Central Government—they say that in the monsoon season they let out water and "we have given you the quota and now you do not deserve anything", and when the rabi season comes, they say "no". So, in Delhi, there should be an advisory committee so that they could get something even by paying double the rate. If this is not discrimination, what also is it?

In regard to electricity, in the rural areas, when lakhs and crores of rupees are spent for importing foodgrains, why not electricity be given to the rural areas for the wells? That

would curtail the expenditure to a very great extent and bring prosperity to the people, and we would not be beggars every time and at evey door. I need not dilate upon this. This has been conceded by the hon. Minister. Further, this point has been conceded also by almost all sides of the House and they are all in agreement with it, namely, electricity should be given for small-scale and cottage industry. But in practice, what happens is that it is given in big towns and cities. Therefore, the migration of population from the rural to the urban areas is creating a big problem and in times to come it would become the biggest problem for the country. Therefore, I submit in all sincerity that this should be looked into, and it is a long-term thinking that is required for this subject.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri Gajraj Singh Rao: Only two or three minutes more. Sir. For small-scale and cottage industries, electricity should be given. Because there is hardly any time for me, I shall just mention a few important points now. The Hariana Committee, which was appointed by the Punjab Government, has unanimously reported, and about water, there is a chapter of 40 pages in respect of each district, and they have admitted and the Punjab Government has admitted that gross injustice has been done to these areas. They should get their due. I hope the ministry would take into consideration the Hariana Development Committee's report which was published a few months back. If the slightest consideration is given to it, I am hopeful they would come to the rescue of that *ilaka* and the gross acts of injustice would be rectified. This is a paying concern. Suppose they give electricity. There is the Delhi Urban Development Board; for 75 miles around Delhi, they say it is controlled area. The funniest thing is, at the time of acquisition, a well with electric connection with two or three *marlas* is taken by them for their *kothis*. About the rest of the land which was irrigated, they say, "we are not acquiring them". The BDOs are called in common parlance as Block Dalal Officers. Unless people pay them, they would not forward any paper for cement for well construction or for electricity connection. This is the state of affairs which has brought about food deficiency. It may be explained on the population basis or any other basis, but the real thing is, there is no desire to help the poor people who supply the fighting men and who produce foodgrains. They are neglected and those living in big towns who can make a big row and big capitalists get the electricity. If a scrutiny is made, this would be found correct. I am prepared to substantiate it before anybody.

Out of the Rs. 14 crores which was saved, Dr. Rao promised that Rs. 1 crore or 2 crores would be given for raising the bund of Sahibi nadhi. I remind him of this promise and request him to see that this is done, because it will substantially increase production and sweeten the saline water area.

श्री बज बिहारी मेहरोत्रा (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझ इस मंत्रालय की मांग पर बोलने का मौका दिया है। श्री फखरुद्दीन अली अहमद को जो कि इस विभाग के मंत्री हैं और जिन की काफी तारीफ भी हुई है, मैं सचेत करना चाहता हूं कि जो तारीफ हो रही है वह तभी कायम रह सकती है अगर वह इस विभाग में कुछ कर दिखायें।

आज देश में बिजली की बड़ी मांग है। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यद्यपि वहां पर डेम बने हुए हैं, माताटीला डैम है, रिहांड डेम है, पथरी डैम है लेकिन इसको एक ग्रिड में नहीं मिलाया जा सका है। इसके रास्ते में कठिनाई यह है कि ट्रांसमिशन लाईज के लिए जो तार लगती है उसके लिए पैसा स्टेट सरकार के पास नहीं है। अगर आप

[श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा]

इसकी व्यवस्था कर सके और ये तमाम प्राजैक्ट्स जिस में कानपुर का थर्मल पावर स्टेशन है, हरदुआगंज का है, सहावल वगैरह हैं, इन सब को मिला दिया जाए तो उत्तर प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस हो सकता है और वहां इतनी बिजली उत्पन्न हो सकती है कि देहातों में सिंचाई के कामों में भी उसको सस्ते रेट पर लाया जा सकता है और उत्पादन अन्न का बढ़ाया जा सकता है । यदि सरकार चाहती है कि इस देश में अन्न की जो कमी है उसको पूरा किया जाए और विदेशों को जो करोड़ों रुपया अन्न मंगाने के लिए भेजा जाता है उसको रोका जाए तो वह रुपया इन योजनाओं के ऊपर खर्च करें । उत्तर प्रदेश में अगर ठीक से बिजली की व्यवस्था कर दी जाए तो उत्तर प्रदेश जोकि आज डिफिसिट स्टेट है, अन्न के मामले में सरप्लस स्टेट बन सकता है ।

अभी माननीय डा० के० एल० राव साहब ने कहा कि जहां से हाई टैंशन लाइंज गई हुई हैं वहां से लोग बिजली लें तो सस्ती पड़ेगी और लो टैंशन लाइंज हैं वहां से बिजली मंहगी पड़ती है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां से हाई टैंशन लाइनें गई हुई हैं और वहां आसपास के गांव सभी बिजली चाहते हैं वहां पर अगर देहातों को बिजली दें तो एक कम्पैक्ट एरिया में दें, गांव के गांव जो आसपास बसे हुए हैं उनमें से दें तो सैकड़ों हजारों की तादाद में काश्तकार बिजली लेने के लिए तैयार हो सकते हैं और उसको ले कर अपने कुओं में इस्तेमाल कर सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले वर्ष दो लाख पक्के कुएं बनाये हैं । इस साल वह साठ हजार कूएं बनायेगी । उन कुओं को वह इलैक्ट्रिफाई करना चाहती है । उसके लिए अगर आप ग्यारह करोड़ रुपया प्लान के बाहर से दे सकें तो मैं आशा करता हूं कि बड़ी संख्या में कुएं इलक्ट्रिफाई हो सकेंगे । उत्तर प्रदेश सरकार ने कुओं की बोरिंग करने के काम को भी हाथ में लिया है । सौ के करीब में बोरिंग भी हो चुकी है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समुद्र की तरह से धरती के नीचे पानी है । छोटे मोटे ट्यूबवैल अगर बनायें तो दो सौ और ढाई सौ फीट नीचे पानी मिल जाएगा, अच्छा पानी मिल जाएगा । इस काम के लिए पोर्टेबल रिग्ज मंगा सकते हैं । बड़े रिग्ज की आवश्यकता नहीं है । माननीय केशव देव मालवीय जी ने एक बार इसका जिक्र किया था । उन्होंने कहा था कि बड़ी आसानी से जीपों पर इनको लगा कर काम में लाया जा सकता है । चौबीस घंटे में दो सौ फीट तक इन से बोरिंग कर सकते हैं । इस वास्ते मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस किस्म के रिग्ज मगावें ।

हमारे यहां जिस क्षेत्र में चकबन्दी हो चुकी है । वहां पर एक एक कुआं बोरिंग करके अगर एनरजाइज किया जा सके तो दुगुना और तिगुना अनाज बड़ी आसानी से पैदा हो सकता है ।

अभी यहां हरियाणा का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि सन् 57 की क्रान्ति में उस इलाके के लोगों ने भाग लिया था और उसकी उसको सजा मिल रही है । इसी तरह से उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका है । वहां के लोगों ने सन् 57 की लड़ाई में हिस्सा लिया था । जब उस इलाके के बारे में आवाज उठाई गई तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्पेशल योजना उस इलाके के लिए मेहता कमेटी द्वारा बनवाई और आठ करोड़ रुपया स्वीकार हुआ पांच सालों के लिए । लेकिन अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ही इसको करे, केन्द्र से नहीं मिल सकता है । वही इसका इन्तजाम करे । उत्तर प्रदेश सरकार के पास साधनों की वैसे ही कमी है । फिर अगर कोई योजना यहां से स्वीकार होती है, उसके लिए भी रुपया नहीं दिया जा सकता है तो वह योजना कैसे पूरी होगी । इसका परिणाम तो यही होगा कि जो बैक्वर्ड एरिया है वह बैक्वर्ड बना रहेगा । मैं चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए ।

किसानों के जो पम्पिंग सैट्स लगे हुए हैं उन से लाभ हमारे देश को हो रहा है । लेकिन डीजल आयल पर टैक्स बढ़ा दिया गया है । उसकी वजह से मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सकड़ों की तादाद में ऐसे किसान हैं जिन को पम्प उधार दिये गये हैं लेकिन जोकि तेल मंहगा होने के कारण अपने पम्प्स को चला नहीं पा रहे हैं । मैं चाहता हूं कि इस ओर भी सरकार का ध्यान जाए । जो पानी है उसको लोग किसी न किसी तरह से काम में लाना चाहते हैं । पशियन व्हील लगाकर वे पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं । लेकिन पशियन व्हील बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के पास स्टील की चादरों की कमी है, उसको पूरी स्टील शीट्स नहीं मिलती हैं । पिछले दिनों हमारे विकास मंत्री यहां आए थे । उन्होंने बताया कि उनको दो हजार टन गल्वानाइज्ड शीट्स का कोटा दे सकें पशियन व्हील के लिए तो बहुत बड़े एरिया में पशियन व्हील्ज के जरिये से सिंचाई का काम वहां हो सकता है ।

उन्होंने यह भी बताया था कि सिमेंट की भी वहां कमी पड़ रही है । सिमेंट फ्री तो कर दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को जितना सिमेंट चाहिये उसको पाने में वहां की सरकार को दिक्कत हो रही है । सिमेंट मंहगा होने की वजह से और सिमेंट अवेलेबल न होने की वजह से काम ठप्प पड़ा हुआ है । मैं प्रार्थना करता हूं कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे फैक्ट्री से सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार को सिमेंट मिल सके । ऐसा करके जो पक्के कुओं की योजना वहां चल रही है, उस में सहायता मिलेगी और कुएं आसानी से बन सकेंगे ।

उत्तर प्रदेश में पम्पिंग प्लान्ट्स की भी कमी है । पम्प बड़ी कम तादाद में वहां मिल रहे हैं । केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई ऐसी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में खुलनी चाहिये जहां पर पम्प्स का निर्माण हो, पम्प जहां ढाले जा सकें । इसकी बहुत जरूरत है । वे पम्प सिंचाई के काम में आयेंगे ।

उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड का जो इलाका है वह बहुत ही जरखेज इलाका है । वहां की भूमि बड़ी उपजाऊ है । काली वहां की मिट्टी है और उस में जो भी बीज डाल दिया जाता है बड़ी आसानी से उग आता है । मेहनत भी उस में बहुत कम होती है । लेकिन वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं । सिंचाई के साधन न होने की वजह से उर्वरा भूमि होते हुए भी उस में उपज न हो यह दुर्भाग्य की ही बात है । यदि सरकार वहां पानी की व्यवस्था कर दे तो वह इलाका एक ग्रेनरी साबित हो सकता है, अन्न का भण्डार बन सकता है । माताटीला से जो पानी मिलता है उसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार को विशेष अनुदान दें ताकि वह बुन्देलखंड में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए छोटी छोटी बंधियां बनाकर, तालाब गहरे कर और कुएं आदि बना सके । उत्तर प्रदेश का यह भाग केवल एक ही फसल देता है, रबी की फसल देता है । खरीफ की फसल पूरी नहीं हो पाती है । अगर वहां सिंचाई की व्यवस्था कर दें तो वहां पर धान पैदा हो सकता है, ज्वार बाजरा पैदा हो सकता है, मक्का पैदा हो सकता है और हमें अन्न के मामले में आत्म-निर्भर होने में मदद मिल सकती है । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर जरूर ध्यान देंगे और उत्तर प्रदेश की इस कमी को पूरा करने की कृपा करेंगे ।

जो बांध बनने जा रहा है टोंस और यमुना पर, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस बात का खयाल रखेंगे कि पानी और बिजली दोनों दृष्टियों से उत्तर प्रदेश के साथ न्याय किया जायेगा । अभी जिस राम गंगा बान्ध का जिक्र श्री अचल सिंह ने किया उस के बारे में हम दस वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन वह बनने नहीं आता है क्योंकि पूरा रुपया अलाट नहीं किया जाता है । इस कमी को जल्दी पूरा करना चाहिये । आज बान्ध हैं, नहरें हैं, लेकिन जो नहरे कानपुर से आगे इलाहाबाद तक ले जाई जा चुकी हैं वह सूखी पड़ी हैं और हजारों

[श्री ब्रज विहारी मेहरोत्रा]

एकड़ जमीन पड़ी हुई है जिस को सिंचाई की सुविधायें नहीं मिल रही हैं । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय राम गंगा बान्ध को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे ।

मैं यह भी आशा करता हूं कि माननीय मंत्री के इन तमाम प्रयासों से देश की लाभ पहुंचेगा और वे सभी प्रान्तों के धन्यवाद के भागी बन सकेंगे ।

श्री तुलशीदास जाधव (नांदेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर इरिगेशन ऐंड पावर की डिमांड पर बहुत बहस हो चुकी है, और इस विभाग के खाते के जो दो मिनिस्टर हैं वह बड़े दक्ष हैं । सन् 1965-66 की जो रिपोर्ट है उसको देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने अपने सामने जो ध्येय रक्खा है उसकी पूर्ति करने की वह बड़ी कोशिश करते हैं । रिपोर्ट के पहले चैप्टर में जो फंक्शन्स दिये हैं उसमें बतलाया गया है कि :

"The target of Third Plan irrigation is 19.6 million acres, achievement 18.1 million acres".

तीसरे प्लैन में इरिगेशन का ध्येय 19.6 मिलियन एकड़ का रक्खा गया था उसमें 1.5 मिलियन एकड़ की कमी हुई है । पावर के बारे में 11.00 मिलियन कीलो वाट्स का ध्येय रक्खा गया था जिस में से 10.5 कीलो वाट्स पूरा हुआ । उसमें भी कमी हुई । जो कारण इसके लिये बतलाये गये हैं वे उचित हो सकते हैं । उसकी पूर्ति करने के लिये चौथी पंच वर्षीय योजना में जो अतिरिक्त सिंचाई करने का उद्देश्य रक्खा गया है वह 13 मिलियन एकड़ का है । इस तरह से कुल मिला कर हम ने 19 मिलियन और 13 मिलियन एकड़, अर्थात् 32 मिलियन एकड़ करने का निर्णय किया है । अगर निःसर्ग इसमें आड़े न आ गया तो ो सकता है कि इसकी पूर्ति हो जाये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि दूसरी योजना के आखिर तक 27,000 गांवों का विद्युतीकरण पूरा हो गया था । तीसरी योजना में 20,000 गांवों का विद्युतीकरण करने का निर्णय किया गया था, वह भी पूरा हो गया । उसके बाद भी 19,000 गांव मार्च, 1965 में पूरे किये हैं । 8,800 गांव हमने 1965-66 में पूरे किये । इसके माने यह हैं कि यह गवर्नमेंट जो काम करने का निश्चय करती है उसकी पूर्ति करने की कोशिश भी करती है । इसमें कोई सन्देह किसी को नहीं है ।

जब 1952 में इस विभाग का अलग निर्माण हुआ तब उसका जो उद्देश्य रक्खा गया था वह यह था :

"The Ministry of Irrigation and Power, established as a separate entity in 1952, is responsible for laying down the national policy for the conservation, development and regulation of the country's water and power resources and for the formulation and promotion of the national programme in the field of irrigation, power and flood control."

यह उद्देश्य बड़ा अच्छा है । इसलिये मेरा कहना यह है कि अच्छा उद्देश्य होते हुये आपने अपने सामने जो आंकड़े रक्खे थे उन की पूर्ति करने की आप हमेशा कोशिश करते हैं इसलिये मैं विभाग को धन्यवाद देता हूं । डा० के० एल० राव ने, जो कि इस विभाग के मिनिस्टर हैं, जो सूचना दी है उसको देख कर ऐसा मालूम होता है कि वह इस काम में काफी दिलचस्पी लेते हैं ।

सारे देश के अन्दर जो सिंचाई का प्रतिशत है अगर उसको देखा जाये तो 1940 की कल्टिवेटेड एरिया और इरिगेटेड एरिया का परसटेज इंडिया पाकेट बुक आफ एकानमिक

इन्फार्मेशन में दिया है ; इसके संबंध में मैं ज्यादा आंकड़ों में न जाते हुये कहना चाहता हूं कि सन् 1948–49 में नेट एरिया सोन, टोटल ब्राण्ड एरिया, नेट एरिया इरिगेटेड और ग्रौस एरिया इरिगेटेड के जो आंकड़े हैं उनको देखने से मालूम होता है कि सिंचाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। सन् 1948–49 में जो नेट एरिया इरिगेटेड थी वह 46 मिलियन एकड़ थी और सन् 1961–62 में वह 61.2 मिलियन एकड़ हुई है। इसके माने यह हैं कि इस विभाग ने तेजी से कदम बढ़ाये हैं।

इतनी तेजी से कदम बढ़ाते हुये उसका जो फायदा है वह सब प्रान्तों को मिलना चाहिये। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के ऊपर इस संबंध में कुछ अन्याय होता है। जान बूझ कर यह अन्याय होता है ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन किन्हीं भी कारणों से हो, उस को दूर करने की मैं मिनिस्टर महोदयों से प्रार्थना करता हूं।

जैसे देश की दूसरी बड़ी नदियां हैं वैसे ही महाराष्ट्र के अन्दर कृष्णा और गोदावरी नदियां हैं जो कि महाराष्ट्र से ही निकलती हैं। महाराष्ट्र की पोजीशन देखने से मालूम होता है कि अगर सारे हिन्दुस्तान के सिंचाई के काम को देखा जाये, कि वहां पर सिंचाई सब से कम है। नहरों से 2 से 2½ प्रतिशत लड की सिंचाई होती है, कुंओं से 3 से-3½ प्रतिशत तक की भूमि की सिंचाई होती है। इस तरह से कुल मिलाकर 5 से 6 प्रतिशत तक वहां की भूमि की सिंचाई होती हैं। महाराष्ट्र में कुल मिला कर 25 से 30 प्रतिशत तक भूमि की सिंचाई हो सकती है। महाराष्ट्र के अन्दर अनाज की बड़ी कमी है इसीलिये महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने इस साल यह एलान किया है कि वह दो वर्षों के अन्दर महाराष्ट्र को अनाज के सम्बन्ध में स्वावलम्बी बनायेंगे। मेरा कहना यह है कि अगर निःसर्ग से पानी मिलता है तो उस पानी का उपयोग करने की अनुमति महाराष्ट्र को दी जानी चाहिये। अगर ऐसा नहीं होता है तो महाराष्ट्र के अन्दर पानी के बगैर अन्नोत्पादन और दूसरी चीजों के उत्पादन का काम नहीं नहीं हो सकता है।

कृष्णा और गोदावरी में जो पानी आता है अगर देखा जाये तो वह महाराष्ट्र से ज्यादा आता है। महाराष्ट्र में से कृष्णा नदी में 985 अब्ज घन फुट पानी आता है, मैसूर में से 865 अब्ज घन फुट पानी आता है और आन्ध्र के अन्दर कृष्णा नदी का जो भाग है, उस में 400 अब्ज घन फुट पानी आता है। अगर इस का प्रतिशत निकाला जाये तो 43 प्रतिशत पानी महाराष्ट्र से मिलता है, 39 प्रतिशत मैसूर से मिलता है और 18 प्रतिशत आन्ध्र से मिलता है। हालांकि महाराष्ट्र की ओर से ज्यादा पानी मिलता है। लेकिन फिर भी उस पानी को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता है। यह बात डा० के० एल राव को भी मालूम है और जो नये मंत्री आये हैं उन के सामने भी यह बात आई है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि निःसर्ग से भी जो पानी मिलता है वह महाराष्ट्र में ज्यादा है।

17 39 hrs.

[SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

गोदावरी नदी जो है उस के प्रतिशत को देखने से मालूम होगा कि आखीर में प्राणहिता संगम तक जो पानी आता है उस में महाराष्ट्र में से 555 अब्ज घन फुट, मैसूर में से 40 अब्ज घन फुट और आन्ध्र से 275 अब्ज घन फुट, आता है। अर्थात् इस नदी में ज्यादा पानी महाराष्ट्र से ही आता है। अगर उस का प्रतिशत देखा जाये तो महाराष्ट्र में से 63.9 प्रतिशत, मैसूर से 4.6 प्रतिशत और आंध्र से 31.5 प्रतिशत आता है। इन आंकड़ों को देखने से मालूम होगा कि इन दोनों नदियों में से दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा

[श्री तुलशीदास जाधव]

महाराष्ट्र से ज्यादा पानी आता है, लेकिन महाराष्ट्र को खाद्य उत्पादन के लिये जो पानी मिलता है वह बहुत कम मिलता है । महाराष्ट्र की जो मांग है वह यह है कि इस पानी का बंटवारा ठीक रीति से हो, एक न्यायिक और उचित रीति से हो और वह एक ऐडहाक बेसिस पर न हो कि उसको इतना दे दो और अमुक को उतना दे दो । गुलाटी कमीशन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को पढ़ने से यह मालूम होता है कि महाराष्ट्र की जो पानी की मांग है वह न्यायोचित है । इसलिए जो सैंट्रल गवर्नमेंट यह कहती है कि 400 टी० एम० सी० , 600 टी० एम० सी० या 800 टी० एम० एम ० सी० ले लो , इस रीति से अंदाज से कहना कि ले लो, ऐसा कहना सरकार का उचित व ठीक नहीं है । दरअसल जो हमारी न्यायोचित व उचित मांग है उस के अनुरूप विचार करके देने की आवश्यकता है ।

महाराष्ट्र के इरीगेशन एंड पावर मिनिस्टर श्री शंकर राव चौहान ने असेम्बली में जो भाषण दिया है उस को देखने से यह मालूम होता है कि आंध्र की जो जमीन है उस से जो पानी आता है वह महाराष्ट्र की जमीन से कम है लेकिन इरीगशन में आंध्र से 10 लाख 63 हजार एकड़ जमीन अन्दर से और दूसरी भी 10 लाख 11 हजार एकड़ इरीगेट होती है यानी कुल इस तरह से 20 लाख 54 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई होती है लेकिन पानी जो नदी में गिरता है वह कम है । आंध्र को पानी ठीक मिले उस में हमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन महाराष्ट्र का जो न्याय हिस्सा है वह नहीं मिलता है । इसलिए मेरा कहना यह है कि महाराष्ट्र के बारे में न्याय किया जाये और महाराष्ट्र को उसका उचित हिस्सा मिले । उस के लिये कोई कमेटी मुकर्रर करें जिस से यह सवाल हल हो सके ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ख़त्म करें ।

श्री तुलशीदास जाधव : मेरा कहना यह है कि आंध्र प्रदेश में पानी मिले वहां भी उत्पादन हो जो कि आवश्यक है लेकिन महाराष्ट्र को उसका उचित हिस्सा अवश्य मिलना चाहिए । महाराष्ट्र के अन्दर अकाल की स्थिति रहती है और जरूरत है कि पानी का बंटवारा न्यायोचित ढंग से हो और एक आर्बिट्रेटर ऐपायेंट करें ।

महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सैंटर के पास बहुत से प्रोजेक्ट्स भेजे हैं लेकिन उन को मंजूरी नहीं मिलती है । मैं ने इस बाबत डा० के० एल० राव से बातचीत की । उनका कहना है कि वहां जितने भी प्रौजैक्ट्स आये हैं वह यहां के योग्य इंजीनियरों द्वारा ऐग्जामिन किये जाते हैं । और जब वह उन को मंजूर कर लेते हैं तो सैंटर भी उनको तुरन्त मंजूरी दे दता है । लेकिन कई प्रोजेक्ट्स प्लानिंग कमिशन के सामने पड़े हुए हैं । महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि दोनों नदी से मिलने वाले पानी पर जो प्रोजेक्ट्स भेजे हैं वह मंजूर नहीं किये जाते हैं जब कि यहां यह कह देते हैं कि वह प्रोजेक्ट्स भेजें तो लेकिन हालत यह है कि जो भेजे हैं उन को मंजूर नहीं किया जा रहा है ।

मेरी बिनती है कि यह कृष्णा, गोदावरी के पानी का जो झगड़ा है, उसे सैंट्रल गवर्नमेंट को तुरन्त ही मिटा देना चाहिए । यह देखना उन का फर्ज है कि इस को लेकर आपस में प्रान्तों में झगड़ा न हो जाये । सैंट्रल गवर्नमेंट किसी भी रीति से एक जगह पर बैठ कर इस झगड़े को तय करे और जितने प्रोजैक्ट्स महाराष्ट्र से आयें उनको अगर वह न्यायोचित हों तो मंजूर करें और उसको भरपूर पानी दें । आंध्र को भी आप भरपूर पानी दें हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन देखने की बात यह है कि अगर आंध्र के जो

प्रोजेक्टस बने हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा पानी वह ले लेंगे तो महाराष्ट्र को भरपूर पानी नहीं मिलेगा । मैं इतना ही चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जो पानी की मांग है चूंकि वह न्यायोचित है इसलिए उसे सैंटर को मंजूर करना चाहिए और महाराष्ट्र के साथ उसे न्याय करना चाहिये ।

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): Coming as I do at the fag end of this discussion, I shall be very brief and pointed. I want to preface my submissions in this regard by saying that the slow development of irrigation and power in our country has singularly failed the revolution of rising expectations in our country. Indeed, if one sees the slow pace of growth in these twin fields, one is apt to observe that the revolution of rising expectations appears here to be in the reverse gear, attendant upon which is disillusionment, frustration and bitterness.

I am asure you are aware that not more than 20 per cent of some 280 million acres under food crops in India have any noteworthy access to irrigation facilities in our country. You are also aware that the Plan targets have failed miserably both in the field of irrigation and in the field of power. I would like to read from a summary of the report of the Programme Evaluation Committee, which, I think, constitutes the serverest possible indictment of the working of governmental plans in these two major sectors. This report is the report of a committee appointed under the Planning Commission itself. It is not the report of persons who do not know what they are saying. This is what they have to say. I am quoting from the summary.

> "Almost everybody involved from the planers to the cultivators has been blamed by the Programme Evaluation Committee of the Planning Commission for the indifferent record of performance of the major irrigation projects. The Committee's findings relate to physical, administrative, technical, economic, social and phychological lapses.".

It goes on to say later on:

> "Some of the defects highlighted by the committee are: unimaginative planning, lack of proper assessment of the economic, physical and social factors, absence of synchronisation between the construction of field channels and availability of canal water, difficulties in land acquisition for field channels, engineering problems, financial stringency, lack of proper maintenance, carelessness on the part of the users of water and reluctance on the part of big cultivators to equitable sharing of the irrigated land.".

A more comprehensive catelogue I could not attempt. I am sure the Ministry realises that in fulfilling its basic responsibilities to the priorities that have been accepted in the country, to greater agricultural production in the country, the inputs of power and irrigation are the most important and the most noteworthy. Indeed it is on this note that the report of this Ministry to this House starts. But I am sorry to say that we do not find in addition to this realisation the promise of better performance.

A few days ago, Shri Fakhruddin Ahmed gave a statement to the effect that he had issued directives to his Ministry to prepare a plan for 20 to 25 years to cover the development of irrigation and power in the country. The report in the press was a very sketchy one. I would like to know what the hon. Minister meant by announcing to the people that he had in mind the formulation of a 25-year plan. Was it to integrate and to give an intense perspective to the needs of development in these two fields? Or was it only to postpone and to divert the hopes and expectations that have arisen in our country?

[Dr. L. M. Singhvi]

I should like also to emphasise that there are areas in this country, particularly the vast tracts of Rajasthan which are gaping in distress, disillusionment but with a ray of hope. These areas have been lying fallow and barren for centuries. It is these areas which offer the promise of India's tomorrow, particularly in the field of agriculture, because it is these areas which are not ever densely populated. It is these areas where the soil is of a very fine quality. It is these areas which lie parched and thirsty for want of water and irrigation potential. In village after village that I have visited in Rajasthan in different parts of the State, the one and crucial question, the one and only question that has been posed before me is whether they are going to get water to irrigate their fields, whether they are going to get power to work their wells, whether they are going to have tube-wells dug for lift irrigation for those areas, and whether Government have any sense of urgency in bringing water to those water-thirsty lands. In Rajasthan there is the acutest famine both in the fields of water and power. The power famine has been explained by certain circumstances claimed to be beyond the control of Government, though I am of the view that perhaps power failure in Rajasthan included also faulty planning in the past, but that apart, as I said at the outset, there is not the hope, the promise, the cheer, that this report could bring to this country or to this House.

I should like to know what precisely they propose to do in respect of digging a large notework of tubewells in Rajasthan. Two hundred tubewells for the whole of Rajasthan is a very niggardly allocation, if I may say so.

Shri Brij Raj Singh Kotah: Quite so.

Dr. L. M. Singhvi: Yet, it seems very little thinking has been done by the Government in the field of providing adequate water. There are areas where even drinking water has to be brought in Rajasthan from as far as 15 to 16 miles of distance. This is a situation which is extremely distressing and disappointing.

I should like to know whether the Government have considered a proposal which I had placed before the House on one occasion, a proposal which has the endorsement of scientists and experts like Prof. Martin Jones, of channelising the use of some of the water resources in the water-logged areas of Punjab for the benefit of the areas in Rajasthan.

I should like to know whether the Government proposes with a sense of urgency to set up the Narmada Valley Project about which Mr. Khosla's report holds out so much promise.

I would like to know whether the allocation for tubewells in Rajasthan could be substantially increased in order that this vast land could be utilised for contributing to agricultural development and growth in the country.

I would also like to know as to whether the Government have made any headway in the matter of receiving the Finance Ministry's concurrence to treat the Rajasthan Canal as a national project. A promise was made, and I happened to be present at the time the promise was made when the former Finance Minister visited Rajasthan, that the Rajasthan Canal project would be treated as a national project. This assurance was repeated in the consultative committee and on various occasions later in this House. I would like to know because we are greatly concerned and exercised about the Rajasthan Canal project which holds out great hopes for Rajasthan but which at present is causing a considerable drain on the exchequer of that impoverished State.

One word more and I have done. I would like to know whether any headway has been made in the matter of making atomic power available in the areas of Rajasthan, Punjab, U.P.

Madhya Pradesh and Delhi. A plan was adumbrated not too long ago in respect of making power available from an atomic reactor to be installed in Rajasthan or somewhere in Punjab or Delhi.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Of which Punjab are you talking? Punjab is going to be divided.

Dr. L. M. Singhvi: It is all the same a part of our motherland, and it makes no difference how Punjab is demarcated or how Hariayana is going to be demarcated.

I would also like the hon. Minister, who is himself an engineer, to assure the House that the engineering services in these two fields will be treated with greater respect and greater consideration and always at a par with the administrative services. They have a feeling, and I think they are right, that they have received a somewhat raw and unfair deal.

What is needed is vigour as well as vision. I find both these wanting in the report which has been placed before the House. I hope there would be an infusion of an element, a modicum of vigour and vision when the hon. Minister rises to reply to the debate, so that we may go back with at least a bit of cheer in our hearts about the prospects and promise of irrigation and power development in our country.

सभापति महोदय : श्री योगेन्द्र झा ।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी): मैं प्रतिवाद-स्वरूप नहीं बोलना चाहता हूं और मैं ने इसकी सूचना स्पीकर साहब को दे दी है ।

सभापति महोदय : श्री एन० पी० यादव ।

श्री न० प्र० यादव (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, आप ने घंटों की प्रतीक्षा के बाद मुझे समय दिया इस के लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं ।

मैं आप के द्वारा सिंचाई मंत्री, डा० के० एल० राव, का ध्यान उत्तर बिहार में सीतामढ़ी की ओर दिलाना चाहता हूं । सीतामढ़ी सबडिविजन में एक बागमति नदी है, जो नेपाल की ओर से निकलती है और कोसी नदी में मिल जाती है । इस नदी के पानी में इतनी उर्वरा-शक्ति है कि यदि सिंचाई के लायक एक एकड़ जमीन में पानी दिया जाये, तो उस में पच्चीस, तीस मन धान, पच्चीस मन खिसारी और पच्चीस मन मक्का पैदा होता है । डा० राव ने 1963 में इस नदी का निरीक्षण किया था और उन्होंने लाखों की भीड़ में सीतामढ़ी की जनता को यह विश्वास दिलाया था कि बागमती नदी को चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में लिया जायेगा । लेकिन बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बागमती नदी के बारे में जो स्कीम सैंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन के पास भेजी गई, वह बिहार के वर्तमान मुख्य अभियन्ता, श्री चटर्जी, और बिहार के भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता, श्री अखौरी प्रसाद इन दोनों आदमियों के झंझट में पड़ी हुई है ।

अभी श्री चटर्जी ने जो स्कीम सैंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन के पास भेजी है, उस में बागमती नदी के एक ओर 105 मील का बांध और दूसरी ओर 103 मील का बांध बनाने की योजना है । इस पर करीब करीब तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे । चटर्जी साहब ने अभी उत्तरी बिहार में सिर्फ बांध बनवाया है, लेकिन इन सत्रह सालों में वहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकी है । मैं जानता हूं कि पूर्व की ओर कोसी से सिंचाई होगी और पश्चिम की ओर मोतिहारी, ज़िला गोरखपुर, देवरिया, छपरा और दक्षिणी मुजफ़्फ़रपुर समस्तीपुर का जो भूभाग है, उस में करीब करीब पंद्रह सोलह लाख एकड़ की सिंचाई होगी, लेकिन बीच का जो भू भाग है —दरभंगा से पश्चिम, मोतीहारी से पूर्व, मुजफ़्फ़रपुर से उत्तर का जो

[श्री न० प्र० यादव]

करीब सैंकड़ों वर्गमील का भूभाग है—,जिस की जन संख्या करीब करीब एक करोड़ की है, उस में अभी तक सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है ।

बागमती की स्कीम के द्वारा ही इस इलाके में करीब दो लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई होगी । आज से साठ बरस पहले बागमती नदी से एक नहर निकाली गयी, जिस पर उस समय के करीब एक लाख रुपये खर्च हुए थे । अब भी उस नहर की लम्बाई 11 मील और चौड़ाई 200 फ़ीट की है है । यदि उस नाले के द्वारा बागमती नदी से सिंचाई की व्यवस्था हो, तो करीब 50 हजार एकड़ ज़मीन की सिंचाई की व्यवस्था होगी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी श्री चटर्जी साहब ने बिहार से जो स्कीम सैंट्रल वाटर एंड पावर कमीशन के पास भेजी है, उस में उस महादेव नाले की कोई रूप रेखा नहीं है । मैंने मिनिस्ट्री आफ़ इरिगेशन एंड पावर की कनसल्टेटिव कमेटी में भी डा० राव से यह निवेदन किया था कि उस महादेव नहर की ओर उन को ध्यान देना चाहिये । मेरा निवेदन है कि उस महादेव नहर की तरफ़ डा० राव का ध्यान अवश्य जाना चाहिए । यदि इस समय महादेव नहर की तरफ एक दूसरी नहर बनायी जाये, तो अभी करीब 25 लाख रुपये ख़र्च होंगे । इसलिए आप के द्वारा मेरा डा० राव से यह निवेदन है कि उस महादेव नहर की तरफ़ उन का ध्यान ज़रूर जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अगले दिन अपना भाषण जारी रखें ।

18.01 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE: RIKSHAW-PULLING

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): सभापति महोदय, कल मुझे चार लाख के एक शहर से एक पार्षद ने टेलीफोन किया और बताया कि आज़ादी के एक वर्ष पहले वहां सन् 1945–46 से 1950 तक रिक्शा चालकों की संख्या 679 थी । इसके अलावा दूसरी तरह के रहे होंगे उनको भी आप दस बीस या सौ जोड़ सकते हैं । बाद में भी आपको जोड़ने होंगे । अब 1965–66 में 5898 रिक्शे हैं और 17,910 रिक्शा चालक हैं ।

सभापति महोदय : आप ज़रा एक मिनट ठहरें । अगले दिन जब हाउस मीट करेगा तो यादव साहब की तकरीर के बाद आनरेबल मिनिस्टर की तकरीर होगी ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जो गैर-कानूनी ढंग से, बिना लाइसेंस लिए हुए रिक्शा चलाते हैं या जो रिक्शायें बिना लाइसेंस चलाई जाती हैं, उन्हें मैं इस में शुमार नहीं करता हूं । खाली उनको मैं कर रहा हूं जिन के लाइसेंस हैं । करीब सात सौ रिक्शा थीं आजादी के पहले और अब करीब छः हज़ार हैं । उसी तरह से करीब दो हज़ार रिक्शा चालक थे आजादी के पहले और अब 18,000 हैं । इसका मतलब यह हुआ कि नौ गुना का फर्क पड़ा है । यह भी एक शहर के आंकड़े मिले हैं और श्री लक्ष्मी भूषण वार्ष्णेय, पार्षद, की मदद से इलाहाबाद शहर के जो कि चार लाख का शहर है । ये उतने पूरे न सही लेकिन जहां तक मिल सके हैं, ये हैं । लखनऊ और बनारस के जो आंकड़े मिले हैं वे भी यही हालत बताते हैं । लखनऊ में इस वक्त राम सागर मिश्र जी ने मुझे टेलीफोन से बताया है कि करीब करीब दस हजार रिक्शा के लाइसेंस हैं और आजादी के पहले के मुकाबले में आज उनकी तादाद नौ गुना, दस गुना बढ़ी है । हैदराबाद जैसे शहर में आपको सुन कर हैरत होगी कि कुल आबादी तो चौदह लाख की है और उस में से रिक्शा चालकों की संख्या पचास साठ हज़ार है ।